Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
July-December 2022 3(2), 1425–1432

IMPACT OF COALITION POLITICS ON INDIAN GOVERNANCE

भारतीय शासन व्यवस्था पर गठबंधन राजनीति का प्रभाव

Bishamber [1], Mamta Devi [2]

[1] Research Scholar, Department of Political Science, Maharshi Dayanand University, Rohtak, India
[2] Assistant Professor, Department of Political Science, Maharshi Dayanand University, Rohtak, India

ABSTRACT

English: Forming a coalition government after elections is a feature of the parliamentary system because when no party gets an absolute majority, then many political parties come together to form a coalition government. The word 'coalition' is the translation of the English word coalition. 'Coalition' is derived from the Latin language, which means 'moving forward together'. According to the dictionary, coalition means a body, individuals or states united in a union i.e. an adjustment of different parts. It describes the process of forming an agreement between different political parties. Coalition governments are usually formed when one or more parties within the legislature form a government in alliance with one or more other parties in a parliamentary election to share the duties of governance. Sometimes, such governments emerge to fill a political vacuum in representation and to guarantee political stability, especially where there is severe political fragmentation. Such governments involve forming coalition governments, in which compromise and pragmatism matter more. This is evidenced by the voting results, which culminate in the creation of a common minimum programme. The basis of governance is shared policy and programmes. But with limited interference of the core principles of the other, allowing the partners to maintain their ideological identities. Indian coalition politics is in a constantly evolving form and through flexibility can change the political partners involved in the process. These partnerships can be pre-election, which unite different interests and policy priorities, in order to form a functioning government with the capacity to achieve agreed goals. Post-election partnerships are also frequent in India. Pre-poll alliances are considered more favourable as the parties entering into the alliance agree to go to the polls under one banner, which includes presenting a common manifesto to the voters. On the other hand, post-poll alliances emerge as a power-sharing solution when one party does not have an absolute majority to form the government and continue to rule.

Hindi: संसदीय प्रणाली में चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाना एक विशेषता है क्योंकि जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन सरकार का निर्माण करते है। 'गठबंधन' शब्द अंग्रेज़ी भाषा के 'कोअलिशन' शब्द का अनुवाद है। 'गठबंधन' लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'एक साथ आगे बढ़ना'। शब्दकोश के अनुसार गठबंधन का अर्थ है एक निकाय, व्यक्तियों या राज्यों का एक संघ में एकजुट होना अर्थात् विभिन्न भागों का एक जगह समायोजन है। यह विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एक समझौता बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। गठबंधन सरकार आमतौर पर तब बनती है, जब विधायिका के भीतर एक या एक से अधिक दल संसदीय चुनाव में एक या एक से अधिक अन्य दलों के साथ गठबंधन करके शासन के कर्तव्यों को साझा करने के लिए सरकार बनाते हैं। कभी-कभी, ऐसी सरकारें प्रतिनिधित्व में राजनीतिक शून्य को भरने और राजनीतिक स्थिरता की गारंटी देने के लिए उभरती हैं, खासकर वहां जहां गंभीर राजनीतिक विखंडन होता है। ऐसी सरकारों में गठबंधन सरकार बनाना भी शामिल है, जिसमें समझौता और व्यावहारिकता अधिक मायने रखती है। इसका प्रमाण मतदान परिणाम से मिलता है, जो सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम बनाने में परिणत होता है। शासन का आधार साझा नीति और कार्यक्रम बनता है। लेकिन गठबंधन दूसरे के मूल सिद्धांतों के सीमित हस्तक्षेप के साथ भागीदारों को अपनी वैचारिक पहचान बनाए रखने की अनुमति देता है। भारतीय गठबंधन राजनीति निरंतर विकास स्वरूप में है और लचीलेपन के माध्यम से प्रक्रिया में शामिल राजनीतिक भागीदारों को बदल सकता है। ये साझेदारियां चुनाव-पूर्व हो सकती हैं, जो विभिन्न हितों

Corresponding Author
Bishamber, bishamberda02@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v3.i2.2022.6258

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2022 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

और नीतिगत प्राथमिकताओं को एकजुट करती हैं, ताकि सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता वाली एक कार्यशील सरकार बनाई जा सके। भारत में चुनाव-पश्चात साझेदारियां भी अक्सर होती हैं। वैसे चुनाव-पूर्व गठबंधन को अधिक अनुकूल माना जाता है क्योंकि गठबंधन में शामिल होने वाली पार्टियाँ एक बैनर के तहत चुनाव में जाने के लिए सहमत होती हैं, जिसमें मतदाताओं के लिए एक साझा घोषणापत्र प्रस्तुत करना शामिल होता है। दूसरी ओर, चुनाव-पश्चात गठबंधन सत्ता साझा करने के समाधान के रूप में सामने आते हैं, यह तब जब एक दल के पास सरकार बनाए रखने और शासन जारी रखने के लिए निश्चित बहुमत संख्या नहीं है।

Keywords: Coalition Government, Power-Sharing, Parliamentary Democracy, Political Alliance, Common Minimum Programme, Pre-Poll Alliance, Post-Poll Alliance, Indian Politics, Governance Stability गठबंधन सरकार, सत्ता-साझाकरण, संसदीय लोकतंत्र, राजनीतिक गठबंधन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, चुनाव-पूर्व गठबंधन, चुनाव-पश्चात गठबंधन, भारतीय राजनीति, शासन स्थिरता।

1. प्रस्तावना

भारत एक लोकतान्त्रिक देश है जिसका सुपरिभाषित संविधान है। इसी संविधान से हमें सरकार चुनने का अधिकार मिला है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों की उपस्थिति में ही कार्य कर सकता है। लेकिन भारतीय संघ बनने के समय जो समस्याएं थी, वही समस्याएँ आज भी संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार बनाने की भी है क्योंकि भारत संघ में धर्म, जाति, नस्लीय, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता इत्यादि से पहचान और उप-पहचान के आधार पर समुदाय और वर्ग बने हुए है। यही समुदाय एवं वर्ग अपने प्रतिनिधित्व के लिए इन्हीं आधारों पर राजनीतिक दलों का निर्माण करते है। इसी बहुदलीय व्यवस्था में जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तब गठबंधन सरकार का निर्माण होता है।

गठबंधन सरकार लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई है। गठबंधन की परिस्थितियों में कई राजनीतिक दलों के समर्थन से संयुक्त रूप से सरकार बनाने के व्यावहारिक पहलू के लिए एक विधिवत रूप में कार्य करना पड़ता है। गठबंधन शब्द अंग्रेज़ी भाषा के 'कोअलिशन' शब्द का अनुवाद है। गठबंधन लैटिन भाषा से लिया गया है इसका शाब्दिक अर्थ है 'एक साथ आगे बढ़ना'। शब्दकोश के अनुसार गठबंधन का अर्थ है एक निकाय, व्यक्तियों या राज्यों का एक संघ में एकजुट होना अर्थात् विभिन्न भागों का एक साथ समायोजन है।

गठबंधन एक विशेष उत्पति है जो राजनीतिक तरीके को दर्शाती है जिसमें विभिन्न राजनीति दल एक वास्तविक राजनीतिक निकाय बनाने के लिए खुद को एकजुट करना संभव बनाते है। गठबंधन सरकारें बहुआयामी होती हैं और राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे के कारण लगातार विकसित होती रहती हैं। एक दलीय प्रणाली के निश्चित स्थिरता आधार के विपरीत, गठबंधन प्रत्येक भाग लेने वाले दल द्वारा सहमत न्यूनतम साझा कार्यक्रम के भीतर काम करते हैं। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है जो गठबंधन के कार्य को आकार देता है। लेकिन यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक दल को उन राजनीतिक प्रणालियों के घटकों को बनाए रखना चाहिए, जिनका वे समर्थन करते हैं। आदर्श रूप से ऐसे अधिकतर गठबंधन तरल और गतिशील प्रकृति के होते हैं। इसलिए भागीदार दूसरे पक्ष में जा सकते हैं या गठबंधन के मजबूत समायोजन के लिए फिर से बातचीत कर सकते हैं। भारत में नब्बे के दशक के उत्तरार्ध के दौरान और उसके बाद के राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन की राजनीति एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभरी है। भारतीय शासन व्यवस्था में कई राजनीतिक दल हैं और मतदाताओं का व्यापक प्रतिनिधित्व भी दलों के लिए सुनिश्चित जीत को जटिल बनाता है। इसलिए राजनीतिक दल राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर गठबंधन सरकार बनाते हैं। अल्पकालिक गठबंधन का एक स्वरूप जो बहुत लाभ देने वाला पाया गया है। वह चुनाव पूर्व गठबंधन है जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को प्रस्तुत करने के लिए मुद्दों की एक एकल और मिश्रित घोषणापत्र पर सहमत होती हैं। दूसरी ओर चुनाव के बाद की रणनीति तब बनाई जाती है जब चुनाव नतीजों में किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता हैं। इसी कारण अनेक दल एक साथ आकर सरकार बनाते है। ये गठबंधन स्पष्ट रूप से अधिक रणनीतिक प्रकृति के होते हैं। यह आधुनिक लोकतंत्रों में बहुमत बनाने की आवश्यकता की वास्तविकता भी है।

गठबंधन सरकारों के कामकाज और उसके प्रभाव को समझना राजनीति की समझ रखने वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह बहुदलीय प्रणालियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति वाले राजनीतिक लोकतंत्र में वास्तविक कार्य प्रणाली, वार्ताओं और परिस्थितियों के प्रबंधन को दर्शाता है। सौभाग्य से गठबंधन गठन और इसके निहितार्थों की प्रस्तुति भारत के लोकतंत्र और सहकारी राजनीति की वास्तविक समस्याओं की गहरी समझ दे सकती है। यह पेपर गठबंधन सरकारों की अवधारणा, आवश्यकता और भारत के विशेष संदर्भ में इसकी रणनीतिक प्रासंगिकता को समझाने का प्रयास करता है।

2. उद्देश्य

1) गठबंधन सरकारों की संरचना और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना:- गठबंधन सरकारों के गठन, निर्णय लेने और शासन में राजनीतिक अभिनेताओं प्रभाव के बारे में जानना।
2) शासन स्थिरता और नीति कार्यान्वयन पर गठबंधन राजनीति के प्रभाव का मूल्यांकन करना:- राजनीतिक स्थिरता, नेतृत्व दक्षता, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीतियों की सामंजस्यता आदि विषयों में गठबंधन राजनीति के फायदे और नुकसान की जाँच
3) गठबंधन राजनीति और संघीय गतिशीलता को आकार देने में क्षेत्रीय दलों की भूमिका का पता लगाना:- विशेष रूप से गठबंधन सरकारों के गठन, केंद्र और राज्य स्तरों के बीच सत्ता संबंधों और संघवाद के बेहतर विस्तृत और अधिक समावेशी ढांचे पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभावों का विश्लेषण करना।

3. भारत में गठबंधन सरकारों का गठन

गठबंधन राजनीति का भारत से खास संबंध है क्योंकि भारतीय राजनीति काफी जटिल और गतिशील प्रकृति की है। भारतीय राजनीति क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आधार पर बिखरे हुए जनादेश के कारण सरकारी गठबंधनों के गठन की विशेषता वाले विभिन्न प्रकार के गठबंधन संयोजन पेश करती है। यह प्रवृत्ति वास्तव में आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी गठबंधन सरकार (1977-1979) से शुरू हुई। चरण सिंह ने इस गठबंधन के साथ (1979-1980) तक जनता पार्टी (सेक्युलर) का गठन किया। लेकिन जनता पार्टी का शासन काफी संक्षिप्त था। दूसरे प्रकार के गठबंधन का पता वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन(1989-1990) में लगाया जा सकता है। जिसे एक साझा एजेंडे के जवाब में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक कार्य करने वाले गठबंधन के रूप में देखा जा सकता है। गठबंधन सरकारों की परंपरा का पालन करते हुए, केंद्रिय स्तर पर चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली जनता दल (समाजवादी) भी 1990 से 1991 तक सक्रिय रही। 1996 से 1998 तक चले संयुक्त मोर्चा गठबंधन में एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल के नेतृत्व में अपेक्षाकृत छोटी पार्टियों के गठबंधन का स्पष्ट उदाहरण हैं। हालांकि यह कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन (1997-1998) के गठन ने अपने तरीके से गठबंधन राजनीति की नींव रखी। हालांकि वाजपेयी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए)(1999-2004) को अधिक स्थिर कहा जा सकता है। इसने सरकार के स्थायी रूप में गठबंधन के बारे में व्यावहारिक स्तर स्थापित किया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने 2004-2014 तक दो कार्यकालों के लिए एक राष्ट्रीय दल और अनेक क्षेत्रीय दलों के गठबंधन को शामिल किया, जिससे सत्ता के रूप में गठबंधन की स्थिरता का पता चलता है। 2014 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को आसानी से एक मजबूत गठबंधन सरकार के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एनडीए ने दोनों सदनों में वोटों का एक स्थिर और ठोस ब्लॉक और केंद्रीकृत नेतृत्व बनाए रखा है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि राजनीतिक गठबंधन की नीतियां भारतीय राजनीति की संसदीय प्रणाली में एक निरंतरता और अपरिहार्य आवश्यकता हैं और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को निर्धारित करती हैं।

4. गठबंधन सरकार की मुख्य विशेषताएँ

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक गठबंधन सरकार अपने काम और बातचीत को परिभाषित करने वाली कई विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे पहले ऐसी सरकारें भौतिक या सत्ता लाभ प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से तब होता है, जब सत्ता विभाजित हो या कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त न कर सके। गठबंधन में दो भागीदारों की उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता है क्योंकि यह अस्थायी और एकल हितों की अनुकूलता पर आधारित है। गठबंधन राजनीति की प्रकृति अस्थिर है अर्थात यह हमेशा राजनीतिक प्रणालियों में स्थितियों के अनुकूल होने और बदलने के साथ ही बनती और बिगड़ती रहती है। गठबंधन सरकार से निपटने के लिए समझौता एक आवश्यक तत्व है, इसलिए वैचारिक कठोरता अव्यावहारिक है। इसके विपरीत गठबंधन न्यूनतम समझौते पर काम करते हैं क्योंकि उनके लक्ष्यों में गठबंधन के सदस्यों के साथ साझा हितों को आगे बढ़ाना भी शामिल है। परन्तु ये साझा हित सभी सदस्यों की सम्पूर्ण नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। राजनीति विजय प्राप्त करना गठबंधन राजनीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। गठबंधन राजनीति में समझौता एक सामान्य विशेषता है जहाँ जीत के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण सत्य को त्यागना पड़ता है। गठबंधन की राजनीति के अस्तित्व का मुख्य कारण सत्ता हासिल करना और उसे बनाए रखना है। भारत में चुनाव-पूर्व और चुनाव-पश्चात स्वस्थ गठबंधन बनाए गए हैं। चुनाव-पूर्व गठबंधन संयुक्त रूप से प्रस्तुत घोषणापत्रों के माध्यम से मतदाताओं से संपर्क करने के लिए एक समन्वित आधार प्रदान करते हैं, जबकि चुनाव-पश्चात गठबंधन सत्ता साझा करके सरकार बनाने में सक्षम होते हैं।

गठबंधन सरकार एक गैर बहुमत सरकार होती है जिसकी विशेषताएँ उसके गठन,गतिविधियों और स्थिरता को परिभाषित करती हैं। गठबंधन शासन का प्रमुख फायदा यह है कि यह समाज के लगभग सभी वर्गों को आसानी से संगठित कर सकता है। गठबंधन सरकारें एक दलीय बहुमत सरकारों से मुख्य रूप से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें कई दलों के राजनेता शामिल होते हैं, जो प्रत्येक राजनीतिक दलों के कई लक्ष्यों के साथ लेकर आते है। इस

तरह के खुलेपन से सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को राजनीतिक और नीति-निर्माण क्षेत्र में लाने की संभावना होती है और इस प्रकार सरकार के निर्णय सर्वव्यापी होते हैं। चूंकि गठबंधन सरकार के गठन में समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए गठबंधन सरकार के लिए लोगों की यथासंभव विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों और मांगो को सूचीबद्ध करना आसान होता है।

गठबंधन सरकार के रूप में एक और उल्लेखनीय पहलू अल्पसंख्यकों और वंचित लोगों के लिए अवसर प्रदान करने का प्रयास है। इन पीड़ित समूहों के पास लड़ने का मौका होता है क्योंकि इन समूहों और आंदोलनों का गठन करने वाली छोटी या क्षेत्रीय पार्टियों को सरकार में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। यह इस अर्थ में और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके मुद्दों को सुना जाएगा और उन पर भरोसा किया जाएगा। जिससे वंचितों के लिए राजनीतिक तर्क संगतता बढ़ेगी। गठबंधन में कई भागीदारों की भागीदारी से संवाद भी महत्वपूर्ण होता है जो आबादी में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतरों को पहचानता है। ऐसे गठबंधनों में नीतिगत निर्णय सभी अलग-अलग और विविध श्रेणियों पर विचार करने का परिणाम होते हैं। साथ ही यह उन नीतियों को हतोत्साहित करता है जो आबादी के कुछ वर्गों को बहिष्कृत और हाशिए पर ले जाती हैं।

लोकतंत्र के एक दलीय स्वरूप की तुलना में गठबंधन सरकार निर्णय लेने की प्रक्रिया जाँची और अधिक संतुलित होती है। निर्णय आम तौर पर गठबंधन भागीदारों के सदस्यों के बीच बहस, सौदेबाजी और सामंजस्य का परिणाम होते हैं। सहकारी मॉडल को लागू करने से दलों को समझौता उन्मुख होने में मदद मिलती है। जिससे ऐसी नीतियाँ बनती हैं जो प्रतिकूल वातावरण में उत्पादित नीतियों की तुलना में अतिरिक्त देखभाल से सूचित होती हैं। यह फायदेमंद है क्योंकि इसका परिणाम कम कट्टरपंथी और अधिक मध्यम मार्ग की नीतियों के रूप में हो सकता है। क्योंकि परिवर्तन के लिए आवश्यक गठबंधन सदस्यों के बीच असहमति के कारण चरम नीतियों को शायद ही कभी अनिश्चित काल तक अपनाया जाता है। यह प्रक्रिया नीतिगत अवरोधो को रोकने और निर्णय लेने में स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी-कभी यह प्रक्रिया धीमी भी हो सकती है। क्योंकि स्पष्ट वैचारिक स्थिति गठबंधन राजनीति के ढांचे में व्यावहारिक सहयोग को परिभाषित नहीं करती है।

गठबंधन राजनीति में सरकार के गठन में कुछ सिद्धांतों के साथ समझौता करना शामिल है ताकि गठबंधन में सभी दलों द्वारा समर्थित कार्य समाधानों पर सहमति हो सके। यह लचीलापन गठबंधन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी के अलग-अलग राजनीतिक एजेंडे होते हैं। गठबंधन आम तौर पर सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करते हैं। जो भागीदारों द्वारा कार्यान्वित और सहमत कार्य योजना और रणनीतियों को दर्शाता है। भले ही यह कार्यक्रम प्रत्येक सदस्य दलों की व्यक्तिगत दलों की योजनाओं के अनुकूल न हो। लेकिन यह शासन के लिए एक कार्यात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

गठबंधन कभी भी स्थायी और निश्चित नहीं होते हैं क्योंकि समय और स्थितियों के अनुसार बदल जाते है। इसका मतलब यह है कि सदस्य दल राजनीतिक घटनाओं और नीतिगत मुद्दों के कारण गठबंधन में आ भी सकते है और जा सकते हैं। जिसके परिणामस्वरूप गठबंधन राजनीति में निरंतर गतिशीलता होती है। संरचनाओं में यह लचीलापन निरंतर सोदेबाजी और गठबन्धनो के परिवर्तन के साथ मेल रखता है। जो एक विषम और जटिल संसद प्रणाली में कार्यशील बहुमत बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गतिशीलता यह गारंटी देती है कि गठबंधन सरकार में शामिल दल एक साथ नए राजनीतिक और सामाजिक परिवेशों को आकर्षित करते हैं जिसके कारण ये गठबंधन अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो जाता है और साझेदारों के बीच समझौते कायम नहीं रहते।

5. गठबंधन सरकारों के गठन के कारण

विधायिका के चुनाव में आम तौर पर किसी विशेष राजनीतिक दल के पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के कारण गठबंधन सरकारों के गठन को बाध्य किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप गठबंधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल बहुमत समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। इस प्रकार के गठबंधन सहभागी हित धारकों को कानूनी रूप से पूरी तरह से पहचाने जाने योग्य रहने में सक्षम बनाते हैं जबकि सह शासन की पृष्ठभूमि बनाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में एक ही मंच पर होते हैं। यह व्यवस्था विभिन्न दलों के सदस्यों को नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में संलग्न होने की अनुमति देती है जिसमें उनके आधार और प्रासंगिकता को बनाए रखते हुए पूर्ण परिवर्तन की कमी हो सकती है।

भारत में गठबंधन सरकार के गठन की घटना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाने वाला पहला कारक बहुलवाद है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई भाषाएँ, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताएँ हैं। इस तरह का राजनीतिक बहुलवाद मौजूद होने के कारण राजनीतिक समाज में अलग-अलग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दल शामिल हैं। इसलिए राजनीतिक व्यवस्थाएँ आम तौर पर ध्रुवीकृत होती हैं। इसी कारण चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल स्पष्ट विजेता नहीं होता है जो प्रक्रिया या संभावित रूप से अनुमानित परिणाम पर हावी हो। इसलिए गठबंधन सरकारें इन विभाजनों को एक साथ लाने का एक अधिक यथार्थवादी तरीका बनकर सामने आती हैं क्योंकि विभिन्न राजनीतिक विभाजन वाले समूह एक साथ मिलकर एक कार्यशील सरकार बनाते हैं। गठबंधन प्रणाली की संरचना भारतीय समाज की बहुल जातिय संरचना का चित्रण करती है। जो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप अनिवार्य रूप से एक आवश्यक और उचित राजनीतिक संरचना है।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के एकाधिकार ने भी गठबंधन सरकारों के उत्थान में योगदान दिया। कांग्रेस पार्टी अपने गठन के समय से ही भारत में कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक वर्चस्व रहा। जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों पर अपनी शर्तें थोपती थी। हालाँकि क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ती राजनीतिक चेतना और कांग्रेस पार्टी के पतन के साथ विभिन्न राजनीतिक संरचनाएँ सामने आई, जो राज्य और

स्थानीय स्वायत्तता की माँग कर रही थी। इन क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन प्रणाली को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम पाया। इस तरह से गठबंधन राजनीति ने इन दलों को शासन के मामलों में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया, बशर्ते कि वे अपने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की आवाज़ हों।

भारत में गठबंधन सरकारें बनने का दूसरा कारण देश में मौजूद चुनावी प्रणाली की जटिलता है। स्वतंत्र भारत में संसदीय शासन प्रणाली में फ़र्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था की आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली से सदस्यों का चुनाव सुनिश्चित होता है। यह प्रणाली मतदाताओं के मतपत्रों से उन दलों को चुनाव कराने और विधान सभा में सीटें सुरक्षित करने की अनुमति देती है, जिनका देश में बड़ा समर्थन आधार नहीं हो सकता है। इस तरह के समावेशन से इन दलों को गठबंधन के माध्यम से शासन की भूमिका निभाने की अनुमति मिलती है। जिसके तहत विधायी और कार्यकारी अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव लड़ते हैं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हुए शासन का हिस्सा बनते हैं। इस अर्थ में गठबंधन यह सुनिश्चित करने का एक तरीका बन जाता है कि विभिन्न दलों के सभी प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों पर क्षेत्रीय आधारित छोटे राजनीतिक दलों के साथ विचार किया जाए।

भारत में गठबंधनों को देश की अत्यधिक सन्निहित राजनीतिक संस्कृति से लाभ हुआ है, जहाँ राजनीतिक नेता व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, सामुदायिक लाभ चाहते हैं। इस व्यक्तिवाद के परिणामस्वरूप एक ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल बनता है जिसमें सरकार बनाने में उपयोग किए जाने वाले बहुमत को जीतने के लिए गठबंधन आवश्यक होते हैं। एक ऐसी प्रणाली के रूप में जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल शामिल हो सकते हैं। गठबंधन सरकार के अपने नुकसान भी हैं। अस्थिरता और नीतियों को अपनाने में असमर्थता आदि। क्योंकि सदस्य दलों की प्राथमिकताएँ अलग-अलग हो सकती हैं। फिर भी इस मामले में विफलता इस तथ्य को कम नहीं करती कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बना हुआ है, इससे भी अधिक भारतीय लोकतंत्र भले ही इसकी सफलता और मुख्यधारा की स्थिरता के विरुद्ध अनेक बाधाएं हों। गठबंधन सरकारें लोकतंत्र का सच्चा चित्रण हैं ।

6.गठबंधन सरकारों के विभिन्न चरणों का तुलनात्मक अध्ययन

अगर आप दुनिया भर में तुलनात्मक रूप से देखें तो अनेक तरह के गठबंधन हैं। पहला जिसे न्यूनतम जीतने वाला गठबंधन कहा जाता है जिसमें केवल बहुमत पाने के लिए पर्याप्त पार्टियाँ होती हैं, कोई अतिरिक्त पार्टियाँ नहीं होतीं जो बहुमत के लिए ज़रूरी नहीं होतीं। दूसरे ऐसे गठबंधन होते हैं जिन्हें अल्पसंख्यक गठबंधन कहा जाता है। 1977 से आज तक भारत में 12 गठबंधनों में से आठ अल्पसंख्यक गठबंधन रहे हैं। यह वह स्थिति है जब गठबंधन अग्रणी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी दल बहुमत से कम होते हैं और उन्हें बाहरी समर्थन की आवश्यकता होती है।

भाजपा के नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एनडीए (1998-2004)के पास लोकसभा में बहुमत नहीं था। वाजपेयी सरकार के पास 182 सीट और अपने सहयोगियों के साथ के साथ बहुमत का आंकड़ा 272 से कम था। इसे तेलुगु देशम पार्टी से बाहरी समर्थन की आवश्यकता थी। तेलुगु देशम दल उस समय एक तरह से एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन यह मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं थी। यदि आपके पास मंत्री पद नहीं हैं तो आपको संसद में विधायी गठबंधन का हिस्सा माना जाता है न कि कार्यकारी गठबंधन। इसे ही अल्पसंख्यक गठबंधन कहा जाता है। वाजपेयी का एनडीए एक अल्पसंख्यक गठबंधन था। ऐसा ही गठबंधन यूपीए-1 भी था जो वाम मोर्चे से बाहरी समर्थन पर निर्भर था। यूपीए-2 जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बाहरी समर्थन पर निर्भर था। हमारे पास 12 गठबंधन सरकारों में से आठ अल्पसंख्यक गठबंधन हैं। और हमारे पास तीन ऐसे गठबंधन हैं जिन्हें अति आकार का गठबंधन कह सकते है। अति आकार का गठबंधन वे होते हैं जहां अग्रणी दल के पास खुद बहुमत होता है लेकिन फिर भी सहयोगी दलों आमतौर पर चुनाव पूर्व सहयोगियों को मंत्रालय में रखता है। उदाहरण के लिए 2014 और 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों में भाजपा के पास साधारण बहुमत था फिर भी उन्होंने अन्य दलों को मंत्रालय में रखा और उन्हें मंत्री पद भी दिए। इसी तरह 1977 में जनता पार्टी जो तकनीकी रूप से एक एकीकृत पार्टी के पास उस समय 295 सीटो का बहुमत था। लेकिन उनके पास बाहरी भागीदार के रूप में अकाली दल था इसलिए तकनीकी रूप से यह एक अति आकार का गठबंधन बन गया। पश्चिम बंगाल में कई विधानसभा कार्यकालों के लिए कुल मिलाकर 34 वर्षों तक वाम मोर्चा की सरकार थी। उस समय के अधिकांश समय के लिए सीपीएम (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी) के पास विधानसभा में अपने दम पर बहुमत था। लेकिन उन्होंने सीपीआई, आरएसपी और अन्य को मंत्रालय में गठबंधन सहयोगी के रूप में रखा। कभी-कभी बड़े आकार के गठबंधनों को बहुमत वाली पार्टी के साथ अधिशेष बहुमत गठबंधन कहा जाता है।

लोकसभा चुनाव 2024 इस मायने में अलग है कि आपके पास बहुमत वाली पार्टी के बिना एक अतिरिक्त बहुमत वाला गठबंधन है। इस गठबंधन की अग्रणी पार्टी भाजपा के पास 240 सीटें थीं जो बहुमत से 32 कम थीं लेकिन उसके पास 272 के लिए आवश्यक संख्या से ज़्यादा गठबंधन सहयोगी हैं। इसमें एनडीए 543 सीटों में से 293 सीटें हासिल की। बहुमत का आंकड़ा 272 तक पहुँचने के लिए भाजपा के पास 240 के साथ-साथ टीडीपी की 16, जेडीयू की 12 और शिवसेना की सात सीटें ही काफी थी। इन तीनों के साथ भाजपा बहुमत के आंकड़े 272 तक पहुंच सकते थे लेकिन एन डी ए गठबंधन ने मंत्रालय में अतिरिक्त पार्टियों को भी शामिल कर लिया। इसी कारण यह गठबंधन भी एक अतिरिक्त बहुमत वाला गठबंधन है जहां अनावश्यक भागीदार हैं। 1977 के बाद से भारत में हुए 12 गठबंधनों में से यह अपनी तरह का पहला गठबंधन है।

7.गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव

भारत में गठबंधन राजनीति का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका मजबूत हो गई है। ये दल स्थानीय और राज्य उन्मुख संस्थाएँ होने के कारण बहुत सीमित परिधि में काम करते हैं। जो अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के बजाय क्षेत्रीय हितों से चिपके रहते हैं। यह इस तथ्य पर आधारित है कि उन्हें राज्य स्तर पर सत्ता की आवश्यकता होती है और इसलिए वे इस शक्ति को बनाए रखने और प्राप्त करने के लिए लोकलुभावन उपाय करेंगे। इस प्रकार अल्पसंख्यकों सहित सभी राजनीतिक ताकतों को सरकार में शामिल करके समावेशिता को बढ़ाते हुए, गठबंधन की प्रणाली ही शासन की रूपरेखा को विकृत करती है। राष्ट्रीय महत्व के कुछ मुद्दों को अनदेखा किया जा सकता है क्योंकि सरकार में भागीदार क्षेत्रीय दल ऐसे उपाय अपनाना चाहते हैं जो केवल उनके राज्यों के हितों पक्ष में हों।

क्षेत्रीय दलों ने इतनी लोकप्रियता हासिल की है और देश के केंद्रिय निर्णय-निर्माता के रूप में केंद्र की जगह ले ली है। यह हस्तांतरण एक दोधारी तलवार है। एक ओर, यह शासन की अधिक भागीदारी वाली प्रणाली में समर्थन लाता है क्योंकि यह क्षेत्रीय अधिकारों और उनके लोगों की आवाज़ को बढ़ाता है। साथ ही यह केंद्र सरकार की शक्ति को कम कर सकता है और एकल राष्ट्र की नीति बनाने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। यह जानते हुए कि क्षेत्रीय दल अधिक प्रभावी राजनीतिक बहस को सामने लाते हैं, वे गठबंधन को अस्थिर भी कर सकते हैं। इसी कारण से उनके मजबूत स्थानीय जनादेश गठबंधन भागीदारों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए प्रधानमंत्री की क्षमता को सीमित करते है। जिससे नीतिगत विचलन को बढ़ावा मिलता है। यह विचलन सरकार को राष्ट्र के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखने के विचार को जटिल बनाता है और विधायी स्थिरता और नीतिगत ठहराव को भी खतरे में डालता है।

वास्तव में गठबंधन सरकार में शामिल होने वाले क्षेत्रीय दलों ने अक्सर सत्ता बदली है क्योंकि इन समूहों को गठबंधन सरकारों में शामिल न होने पर शायद ही सत्ता मिल पाती। यह तर्क दिया गया है कि इस वजह से गठबंधन प्रणाली अलोकतांत्रिक है क्योंकि छोटी पार्टियों के पास सता की कुंजी है। ऐसी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं क्योंकि वे केंद्रीय बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदर्शन को खतरे में डाल सकती हैं और उतार चढ़ाव पैदा कर सकती हैं। फिर भी क्षेत्रीय दलों ने देश की आबादी के व्यापक आधारित प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर भारतीय राजनीतिक प्रणाली में लोकतंत्र को एक नये स्तर पर ला दिया है। आज वे बोल सकते हैं और उनकी आवाज़ कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर सुनी और मानी जा सकती है।

8.प्रधानमंत्री के नेतृत्व और शासन के लिए चुनौतियाँ

एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो गठबंधन सरकारों को प्रभावित करता है वह प्रधानमंत्री या निर्वाचित कार्यकारी शाखा के प्रमुख का नेतृत्व। गठबंधन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को एहसास होता है कि उसके पास कुछ ऐसी बाधाएँ हैं जो उसे अपने दम पर निर्णय लेने से रोक सकती हैं। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि सरकार की स्थिरता पूरी तरह से गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर करती है। अगर वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। इस तरह का माहौल एक राजनीतिक सोदेबाजी को बढ़ावा देता है जिसमें प्रधानमंत्री को गठबंधन में विभिन्न दलों के लोगों को समायोजित करने और गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक समझौते करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो नेतृत्व को बहुत कमज़ोर कर देता है।

इस संबंध में संघर्ष का दूसरा क्षेत्र वह है जहाँ प्रधानमंत्री को गठबंधन सरकार में कैबिनेट के गठन और प्रबंधन से निपटना पड़ता है। यह एक दल के बहुमत की स्थिति से अलग है जहाँ प्रधानमंत्री अपनी योग्यता या विश्वसनीयता के आधार पर पसंदीदा मंत्रियों की एक टीम चुन सकता है। गठबंधन में मंत्रिमंडल अक्सर गठबंधन के सदस्यों के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप पूर्व निर्धारित होता है। बेशक इसका मतलब यह है कि मित्र उम्मीदवारों को पद दिए जा सकते हैं भले ही उनके पास मंत्री पद या पोर्टफोलियो क्षमता हो या ना हो। बहुसदस्यीय गठबंधन में हितों का टकराव अंतर्निहित हैं। जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है साथ ही सुसंगत और प्रभावी नीतियों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की क्षमता को कम कर सकता है। वे नीति- निर्माण और शासन प्रक्रिया को भी शामिल करते हैं। गठबंधन सरकार में प्रमुख नीतियों को लागू करने से पहले प्रधानमंत्री को गठबंधन के घटक दलों की सहमति लेनी होगी। इसके कारण अनुमोदन पर निर्भर रहने की यह प्रवृत्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी कर सकती है और साथ ही अप्रभावी या अप्रामाणिक नीतियाँ दे सकती है। गठबंधन भागीदारों को खुश करने के लिए यह व्यवस्था लगातार प्रधानमंत्री के अधिकार को कम करता है। परिणामस्वरूप घरेलू और विदेशी नीतियों से समझौता किया जाता है। यह राजनीतिक गतिरोध को भी प्रभावित कर सकता है जिससे गठबंधन की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी या कमजोर हो जाती है। हालांकि इसे गलत नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि शासन के मामले में गठबंधन की राजनीति के भी अपने फायदे भी हैं। यह इस तरह विचारों और समझौतों की पीढ़ी के प्रवाह को बढ़ावा देता है जो हमारी दुनिया में बहुत अधिक निष्पक्ष हैं क्योंकि उन पर अच्छी तरह से चर्चा की जाती है और उन पर तर्क- वितर्क किया जाता है। बेशक यह बहुत समय लेने वाला हो सकता है। फिर भी विभिन्न हितधारकों को समस्या को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक सटीक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देना अधिक प्रभावकारी हो सकता है।

हालांकि जैसा कि ऊपर वर्णित लगभग सभी लाभों के साथ,संभावित कमियों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किया जाना चाहिए और यह केवल अच्छे नेतृत्व गुणों के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि गठबंधन में एक प्रधानमंत्री को गठबंधन को एक साथ रखने के लिए बातचीत में एक पेशेवर होना चाहिए, साथ ही देश को प्रभावी ढंग से संचालित करना चाहिए।

9. संरचनात्मक बदलाव और भारतीय संघवाद पर प्रभाव

गठबंधन सरकारों के चुनाव के लिए भारतीय संघीय व्यवस्था की संरचना केंद्रीय राज्य और राजनीतिक प्राधिकरण में भी महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होती है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद यह एक केंद्रीकृत प्रणाली थी जहाँ केंद्र सरकार के पास भारत के राज्यों पर बहुत अधिक शक्ति थी। हालाँकि यह गठबंधन की राजनीति के बदलाव के कारण इस व्यवस्था में बदलाव हो गया है। इसलिए संघीय व्यवस्था अधिक सहयोगात्मक हो गई है। यह बदलाव आंशिक रूप से क्षेत्रीय दलों के कारण है, जो अधिक विकेंद्रीकरण की मांग करते हैं और सहकारी व्यवस्था के संबंध में उनके समर्थन के बदले में उनका प्रतिनिधित्व करने की शक्ति को स्पष्ट करते हैं।

गठबंधन के कारण होने वाले इन संरचनात्मक परिवर्तनों के बीच समन्वयक या संचालन समितियों जैसे संविधानेतर निकाय उत्पन्न होते हैं। ये संस्थाएँ आमतौर पर भागीदारों के बीच संदेशवाहक के रूप में महत्वपूर्ण भागीदारी रखती हैं और सामान्य सरकारी नीति-निर्माण प्रक्रिया के बाहर नीतिगत निर्णय लेती हैं। हालाँकि ये निकाय गठबंधन के भीतर समन्वय को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत स्थापित संसदीय लोकतंत्र और कैबिनेट और प्रधानमंत्री की शक्ति को कम करती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि शासन की प्रक्रियाएँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अलग हो जाएगी और पर्दे के पीछे की सौदेबाजी का नतीजा बन जाएंगी।

गठबंधन की राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव भारत में संघवाद के पुनर्गठन पर भी देखा जा सकता है। राष्ट्रीय शासन प्रणाली में क्षेत्रीय दलों को शामिल करने से केंद्र-राज्य संबंधों में समानता लाने में मदद मिली है। अनुच्छेद 356 जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया, लेकिन गठबंधन की राजनीति के प्रभाव के कारण धीरे-धीरे इसमें कमी आई है। जिससे केंद्र सरकार के लिए क्षेत्रीय भागीदारों को नाराज़ करना राजनीतिक रूप से महंगा हो जाता है। इस बदलाव ने सहकारी संघवाद की कहीं अधिक प्रामाणिक शैली को प्रोत्साहित किया है जहाँ चर्चा केंद्र की ओर से दबाव की जगह लेती है। उभरती संरचना बहुलवादी राजनीतिक परिदृश्य और भारत के कई राज्यों की आकांक्षाओं के साथ अधिक तालमेल में हो सकती है ताकि शासन के प्रतिस्पर्धी ढांचे को एकीकृत किया जा सके।

हालाँकि इन परिवर्तनों के संबंध में लोकतांत्रिक अवसरों और खतरों दोनों को देख सकता है। गठबंधन की राजनीति राष्ट्रीय और राज्य की गतिविधियों को भी आपस में जोड़ सकती है और परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के लिए सक्रिय रूप से ठोस राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन और उन्हें लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्षेत्रीय हितों पर जोर का अर्थ यह हो सकता है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का कई बार अच्छी तरह से समन्वय नहीं हो सकता है क्योंकि इससे नीति विखंडन हो सकता है। यह उन मुद्दों से निपटने में विशेष रूप से नुकसानदेह हो सकता है जिनके लिए आर्थिक सुधार राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को गठबंधन द्वारा शासित संगठनों की ताकत बढ़ाने के लिए परिचालन रूपरेखा को स्पष्ट करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। ऐसे उपायों में मंत्रिमंडल का विस्तार करने से बचने के लिए मंत्रालयों के आकार को सीमित करना और बेहतर परिणाम लिए चुनावी प्रणाली को बदलना शामिल है। जिस पर राजनीतिक भागीदार सहमत हो ऐसे समन्वित नीति प्रस्तावों को एक साझा सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम से एक मजबूत और काफी हद तक अधिक एकीकृत दिशा भी दी जा सकती है। इसलिए भारत जैसे लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और उनके संयोजनों के परिवर्तनशील प्रभाव यह हैं कि गठबंधन की राजनीति के अभ्यास में निहित समस्याओं और इस तथ्य के बावजूद कि उप समूह अपनी सदस्यता को उनके और मुख्यधारा के बीच के अंतरों पर आधारित करते हैं जहां शासन के अधिक प्रतिनिधि रूप की संभावना को सही तरीके से प्रबंधित किया जाता सकता है।

10.निष्कर्ष

आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र में उतार चढ़ाव का दौर रहा है। जंहा एक ओर मजबूत सरकारों ने देश हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए तो वंही दूसरी ओर अपनी सत्ता को बचाने और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार अधिनायकवादी प्रवृत्ति को अपनाने से भी नहीं चूकी। आपातकाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आम धारणा है कि गठबंधन अस्थिर होते हैं, लेकिन भारत में स्थिर गठबंधन स्थिर अल्पसंख्यक सरकारें रही हैं। भारतीय गठबंधन राजनीति में चार अल्पसंख्यक सरकारें रही जिनका कार्यकाल पूरे पांच साल का रहा है और वे क्रमिक सुधार और विकास को बढ़ावा देती रहीं। दुर्बल समझे जाने वाले गठबंधन सरकारों के निर्णयों ने भी भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है जिसमें पिछडे वर्गों को आरक्षण देना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना, आर्थिक सुधार आदि। भारतीय राजनीति में उस तरह की अस्थिरता नहीं रही है जिसकी साहित्य में बहुत बड़े बहुदलीय गठबंधनों से अपेक्षा की जाती है । गठबंधन की राजनीति अस्थिर और अक्षम नहीं होनी चाहिए ।

संदर्भ सूची

चक्रवती विदुयुत (2014) कोअलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू दिल्ली।
नकवी सबा (2019) पॉलिटिक्स ऑफ़ जुगाड़. रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्रा. लि. नई दिल्ली।
जैन धर्मचंद (2000) भारतीय लोकतंत्र भाग2ए. प्रिंट वेल पब्लिशर ।

गोस्वामी भालचंद्र (1996) संसदीय लोकतंत्र और उसका विकल्प. पांइंटर पब्लिशर जयपुर राजस्थान।
श्रीधरन ईश्वरन (2024) इलेक्शन पार्टी एंड कोएलिशन इन इंडिया. परमानेंट ब्लैक।
कुमार राकेश (2018) भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारें. नई दिल्ली राजकमल प्रकाशन।
मिश्रा अनिल (2020) भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक दल. जयपुर पिंक सिटी पब्लिकेशन्स।
वर्मा एस.पी. (2017) भारतीय शासन व्यवस्था. नई दिल्ली अवध पब्लिकेशन।
चतुर्वेदी विनोद (2019) गठबंधन राजनीति का बदलता स्वरूप. भारतीय राजनीति पत्रिका
Election Commission of India. (2023) Statistical Reports on General Elections. नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग।
यादव योगेन्द्र (2016) भारत में चुनाव और राजनीति. नई दिल्ली पेंगुइन बुक्स।
Kohli, Atul. (2001). The Success of India's Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
Hasan, Zoya. (2010). Politics of Inclusion: Castes, Minorities, and Affirmative Action. Oxford University Press.
Sridharan, E. (2012). "Coalition Politics in India: Lessons from Theory and Practice". India Review, 11(2), 111–125.
Palshikar, Suhas, & Kumar, Sanjay. (2014). Electoral Politics in India: Resurgence of the Bharatiya Janata Party. Routledge India.
Brass, Paul R. (2011). The Politics of India Since Independence. Cambridge University Press.
Chhibber, Pradeep, & Nooruddin, Irfan. (2004). "Do Party Systems Count? The Number of Parties and Government Performance in the Indian States". Comparative Political Studies, 37(2), 152–187.
Singh, Mahendra Prasad. (2015). Coalition Politics in India: Problems and Prospects. New Delhi: Har-Anand Publications.
Mehta, Pratap Bhanu. (2003). "India's Judiciary: The Promise of Uncertainty". Oxford Companion to Politics in India. Oxford University Press.
Jaffrelot, Christophe. (2012). India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India. Columbia University Press.